Shri S. M. Banerjee: Question No. 73, which is allied to this, may also be taken up with this.

Mr. Speaker: Can they be taken together?

Shri B. R. Bhagat: Yes, if you agree.

Mr. Speaker: Yes.

Purchase of Tyres by Ministry of Defence

+

*58. **Shri Madhu Limaye:**
Shri Yashpal Singh:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Army Headquarters had issued directions that the tyres purchased from the quota imported through the State Trading Corporation (mentioned in the 64th Report of the Public Accounts Committee) should not be sent to the forward areas;

(b) whether these instructions were not carried out by the Ordnance Depots by sending some of these tyres to the forward areas;

(c) whether any action has been taken for violating these specific instructions of the Army Headquarters; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Purchase of Tyres by Ministry of Defence

*73. **Shri Madhu Limaye:**
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the total number of tyres for which orders were placed by the Depots directly or through the Directorate-General of Supplies and disposals from the stock mentioned in the 64th Report of the Public Accounts Committee;

(b) the total amount paid for purchasing these tyres;

(c) whether the orders were for standard tyres or cross country tyres;

(d) whether it is a fact that no inspection or test was carried out of these tyres before accepting them;

(e) whether responsibility of the officers concerned has been fixed in the matter; and

(f) if so, whether any proceedings have been instituted against the persons responsible for these purchases and acceptances?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat): (a) Orders placed by the Central Ordnance Depot, Malad, for 4,400 tyres directly and 7,100 tyres through the Director General of Supplies and Disposals.

(b) Only 9,910 tyres were actually supplied against the orders referred to in (a) above. The total amount paid for these 9,910 tyres is Rs. 34,78,734.

(c) The orders placed by the Central Ordnance Depot, Malad, directly were for Standard Tread Pattern tyres. The order placed by the DGS&D was for Track Hard Road/All Purpose tyres.

(d) Only visual inspection was carried out by the Inspectors. No testing was, however, carried out.

(e) and (f). The matter is still under investigation.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि सैनिक मुख्यालय के द्वारा कोई निदेश नहीं दिये गये—यही कहा है न आपने ?

श्री ब० रा० भगत : जी ।

श्री मधु लिमये : अग्रिम इलाकों में (फारवर्ड इलाकों में) इन टायरों को न भेजा जाय, इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया—ठीक सुना है न मैंने ?

श्री ब० रा० भगत : जी ।

श्री मधु लिमये : तो, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास केन्द्रीय सरकार के तीन खतो की जानकारी है, जिनके नम्बर मैं उन को सुनाये देता हू Army Hqrs letter No 02566/OS/4E dated 17th July 1963; दूसरा है Joint Secretary to the Government of India, No 22(20|632697|D) dated 22nd July, 1963, और तीसरा है Army Order No 375|57 जिस मे मेरी जानकारी के अनुसार साफ कहा गया है कि ये खराब टायर हैं और इन का इस्तेमाल अग्रिम इलाको के लिये (फार्वर्ड इलाकों के लिये) न किया जाय, क्योकि यह चीज खतरे से खाली नही है, और ऐसे इसी माल से राष्ट्र पर बडा सकट गुजर सकता है। इन आदेशो के बावजूद फार्वर्ड एरियाज मे ये टायर भेज दिये गये, इसकी सूची आपकी इजाजत से सदन की टेबिल पर रखना चाहता , करीब करीब 1100 टायर ये हो जाते हैं, मैंने मिलाया नही है, लेकिन 1000 और 1100 के बीच मे हैं । मैं मत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या वे ये तीन पत्र सदन की टेबिल पर रखने के लिये तैयार हैं जिससे कि सदन को पता चले कि वे जो बात कह रहे है, वह सही है या गलत है ।

साथ ही साथ मैं जानना चाहता हू कि इस तरह के आदेशो का उल्लघन करने के कारण क्या सरकार इन सभी अफसरों के खिलाफ जो सेना मे है या मत्रालय में हैं कोई ठोस कार्यवाही करेगी कि . .

Mr. Speaker: You have read it already.

श्री मधु लिमये : मेरे पास तफसील भी है issue voucher, date, to whom issued, quantity यह बहुत जरूरी है ।

श्री ब० रा० भगत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला पब्लिक एकाउन्टस कमेटी मे भी आया था, इस पर उनकी सिफारिश भी है, उन से बातचीत भी चली, उन्होंने भी इन बातो का जिक्र किया है, अब जो यह मामला आया है, इस के बारे मे हम जांच पडताल करेगे और जो कार्यवाही होगी करेगे । पब्लिक एकाउन्टस कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, उन पर विचार कर रहे है और सदन को वह आश्वासन देना चाहता हू कि चाहे कोई अफसर हो या और कोई हो, जो कार्यवाही कानूनी जायज होगी, उनकी सिफारिशो के आधार पर होगी, वह हम करेगे।

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्नो मे से एक का भी उत्तर नही मिला है । पब्लिक अकाउट्स कमेटी के सामने यह बाते नही थी । पब्लिक अकाउट्स कमेटी को इन खतो और परिपत्रो का शायद पता नही था न इस बात का इन आदेशो के बावजूद उन का उल्लघन कर के फार्वड एरियाज को इतने टायर भेज दिये गये हैं। यह नई जानकरी मै नही दे रहा हू । मैं ने पी० ए० सी० रिपोर्ट को पढ़ा हैं।

श्री ब० रा० भगत : मैं ने कहा था कि इन तीनो पत्रो मे जो जानकारी दी गई है उन को देख कर हम इस मामले मे कार्रवाई करेगे ।

श्री मधु लिमये : क्या उस को सदन के सामने रक्खेगे ? पहले तो आप नही बोलते हैं फिर जब हम पत्रो के नम्बर और तारीखें देते हैं

Mr. Speaker: Please put your question.

श्री मधु लिमये : फिर इस तरह के जवाब क्यों दिये जाते हैं कि इस तरह का कोई आदेश नहीं है, कोई इस तरह उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है..

Shri S. M. Banerjee: Place it on the Table.

श्री मधु लिमये : वह तो मैं ने कह दिया कि इसे रक्खूंगा। इस मे कोई छिपी हुई बात नहीं है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पब्लिक अकाउंटस् कमेटी ने अपनी रपट मे जो कई बातें लिखी है उस मे एक बहुत गम्भीर है कि जब यह तय हुआ कि इन टायरो को अग्रिम इलाको मे न भेजा जाय—पहले तो यह निर्णय ही गलत है कि खराब टायर खरीदे जायें चाहे अग्रिम क्षेत्र हो या पीछे का उन को सेना के लिये बिलकुल नही लेना चाहिये—उस मे मेरा ख्याल है कि लाखो रुपये अफसरों ने खाये है। कादिवली मलाड मे एक कमांडिंग अफसर मेजर सिंह साहब हैं, उन्हें सेना मे मुक्त किया गया है। अगर छ महीने समाप्त होने के पहले सरकार कार्रवाई नही करेगी तो उसके बाद नियमानुसार उनके खिलाफ कोई कार-वाई नही की जा सकती। इसी तरह डारेक्टोरेट जनरल आफ स लाईज मे एक बडे अधिकारी गुप्ता नाम के है। उन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ? आर्मी हेडक्वार्टस का जो आदेश था, जो फैसला था, इस के सम्बन्ध मे लोक लेखा समिति ने कहा है कि उस को सात या आठ सप्ताह तक दबाया गया, और यह कारण बतलाया गया कि गृह मन्त्रालय ने उस की फाइल मागी थी। आप नकल गृह-मन्त्रालय को भेज देते और जो उनके पास परिपत्र था उसके आधार पर परिपत्र जारी करते। वह आपने नही किया। उस के बाद उस समय देश मे जो डिफेन्स एण्ड इकनामिक कोआर्डिनेशन मन्त्री थे कृष्णमाचारी साहब .....

Mr. Speaker: This is all history. He should come to the question.

श्री मधु लिमये : इतिहास नही है। इस का साफ जवाब नही आया कि क्या इन सारे मामलों के बारे में कोई कमेटी नियुक्त की जा रही है कि जैसे इम्पात के बारे मे हुई। इस बारे मे मैं जानना चाहता हू कि इन मामलो की जाच करने के लिये कोई जांच समिति नियुक्त की जायेगी ? या क्या इस सुझाव पर विचार किया जायेगा कि जो सुरक्षा मंत्रालय है दूसरे मंत्रालय हैं उन के काम पर निगरानी रखने के लिये इस सदन की स्थायी समितिया हो जैसे कि अमरीका मे सेनेट है या हाउस आफ रिप्रजेन्टेटिव्ज की कमेटिया है ?

श्री ब० रा० भगत : आखिरी बात तो सजेशन फार ऐक्शन है और वह विचार के लिये है। माननीय सदस्य ने जो नाम लिये है उन अफसरो के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है इस की जाच की जा रही हैं। और भी दूसरे अफसरों के बारे में शिकायतें हैं जिन के बारे मे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जिक्र किया है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं मैं यह आश्वासन देता हूं कि उचित कार्रवाई हम करेंगे। पब्लिक अकाउट्स कमटी ने जो सिफारिश की है उस पर गहरे तौर से हम विचार कर रहे हैं और कार्रवाई होगी। इस मे कोई रुकावट नही आयेगी।

श्री यशपाल सिंह : आप अलग अलग कही एस० टी० सी० और कही दूसरे महकमो को इस तरह बीच मे लातें हैं तो क्या हमारे डिफेन्स परपजेज के लिये हमारे पास इतनी वर्कशाप्स नही हैं और मिलिटरी इक्विपमेट ऐसा नही है कि हमे दूसरों का मुहं न देखना पड़े और मिलिटरी की जरूरत मिलिटरी से पूरी होती रहे ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो टायरों का सवाल था। टायर अभी किसी भी आर्डनेन्स फैक्ट्री में नही बनते हैं। जो देश में बनते हैं उन को लिया जा सकता है लेकिन यह टायर

तो उस समय देश में भी नहीं थमते थे इस लिये उन को बाहर से मंगाया गया था।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर आप इजाजत दें तो लोक लेखा समिति रिपोर्ट से मैं आप को दो पैरा पढ़ कर सुना दूं। यह लोक लेखा समिति की रिपोर्ट है।

Mr. Speaker: But ultimately it is the Question Hour.

डा० राम मनोहर लोहिया : इसी पर तो एक यह है: सफा 52।

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में पढ़िये।

डा० राम मनोहर लोहिया : कहिये तो फौरन हिन्दी मे तर्जुमा करता जाऊ, लेकिन इस मे बडी देरी लगेगी।

Shri K. K. Chatterjee: On a point of order. During question hour, he can ask a question. How can he go on reading something?

Mr. Speaker: He is pointing out that part of the PAC report and asking the Minister a question in connection with that part.

डा० राम मनोहर लोहिया : उस के बिना पढ़े हुए सवाल अच्छी तरह से हो नही सकेगा। सदन को मालूम नही है कि लोक लेखा समिति ने आखिर इस मामले में क्या कहा है। वह इस प्रकार है...

श्री शिव नारायण : यह हाउस के सामने हैं इस तरह से कहना हाउस का अपमान करना है।

Mr. Speaker: If every Member begins reading like this, the question hour will be over soon.

डा० राम मनोहर लोहिया : वह खाली स्वर्ग में हैं। लेकिन इस पृथ्वी तल में हर एक सदस्य ने नहीं पढ़ा है।

"It has been stated in the note that the delay in conveying the decision of the Ministry to the DGOF and the DGSD was largely because the file was taken by the Ministry of Home Affairs for investigation on 29th April 1965 and appears to have been received back on 25th June, 1965."

29 अप्रैल से 25 जून तक जहां यह फाईल रहनी चाहिये थी जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत थी वहां न रह कर गृह मन्त्रालय के पास चली गई और फिर उस समिति ने एक नोट मे उल्लेख करते हुए अपनी राय दी है :

"The Committee are unable to appreciate the type of attitude on the part of the DGSD. .."

अब वह ऐटिट्यूड क्या है :

"The consequences of the type going off while a defence vehicle is on the road are serious. Obviously this fact escaped the notice of the officer concerned who passed the order. " (*Interruptions*).

मालूम नही होता कि इस मुल्क को सुधारने की इच्छा इन लोगों की है या नही जाओ मुल्क ने ठुकरा दिया है और आशा है ऐसी ठोकर खाओगे कि याद रक्खोगे। बेमतलब की बातें यह लोग करते हैं। यहा सवाल है देश की रक्षा का। खराब टायर खरीदे जाते हैं। उन की खुद की किताब मे हैं। उस मे से पढ़ कर सुनाता हूं तो यह शुंड चिल्लाने लगते हैं। आखिर किसी तरह की मर्यादा तो होनी चाहिये न।

इस पर मैं पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी घोटाला हुआ है—और मालूम होता हैं कि लाखों का है—उस में गृह मन्त्रालय और रक्षा के कौन कौन अफसर शामिल हैं और जो मेजर सिंह साहब हैं जो छुट्टी ले कर चले गये हैं पलटन से निकल गये हैं,

और पलटन में एक नियम होता है कि छः महीने जब किसी आदमी को निकले हुए हो जाते हैं तो उस के सम्बन्ध में सवाल उठाया नहीं जाता और छः महीने अब खत्म होने वाले हैं ऐसी सूरत में जब इतना बड़ा मामला आप के सामने आयेगा है और लोक लेखा समिति की अपनी राय है कि सब चीजों मे गड़बडी हुई है, फाईलें गायब हुई हैं, कई मन्त्रालयों की साजिश से फायलें गायब हुई हैं, तो मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं (1) कि क्या मेजर सिंह को सेना मे वापस बुला लेगे और उन के ऊपर पूरी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे? (2) क्या इस सम्बन्ध मे कोई समिति सदन की या कोई और बिठला कर के पूरी जाच करायेगें क्योंकि यह सिर्फ रुपयों का ही मामला नही है बल्कि हमारे सामने सैनिक के कत्ल का मामला है।

श्री ब० रा० भगत : जहा तक मेजर सिंह का सवाल है वह छुट्टी पर चले गये है यह ठीक है मगर उन पर कार्रवाई हो सकती है और वह कार्रवाई क्या की जाय इस की छान बीन चल रही है। उन को बुलाने का अभी कोई सवाल नही उठता है।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह छुट्टी पर नही गये हैं वह बिल्कुल मुक्ति पर चले गये है। छुट्टी नही उन की मुक्ति हो गई। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल यहां ही नही रह जाता है आप देखिये। मंत्री महोदय और मेरे कहने मे जमीन आसमान का अन्तर है। मैं ने कहा है कि वह पलटन से चले गये हैं, उन्होंने पलटन से मुक्ति ले ली है और मंत्री महोदय कहते हैं कि वह छुट्टी चले गये हैं। क्या वह वापस आ जायेंगे।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने मुक्ति का शब्द तो अब कहा है।

डा० राम मनोहर लोहिया : छः महीने बाद उन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मंत्री महोदय जरा तसल्ली से मेहरबानी कर के उत्तर दें और कहें कि इस के ऊपर प्रमुख प्रमुख कार्रवाई होगी क्योंकि उन से कम से कम मैं उम्मीद करता हूं कि और मंत्रियों की तरह वे आवेश में उत्तर नहीं देगें, तसल्ली के साथ देगें क्योंकि शायद उन के दिल में देश के लिये टीस है।

श्री ब०रा० भगत : जहां तक सिंह साहब का सवाल है यह बात सही है कि वह मुक्ति कहिये या जिस को अंग्रेजी में कहते हैं—मुझे डा० साहब इस अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करने के लिये माफ करें—प्रिमैच्योर रिटायरमेट, लेकर चले गये हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात सोची जा रही है। उनका अगर इस में हाथ है और वह साबित हो जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह तो एक औजार है, उन से भी बड़ों का हाथ है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मन्त्री महोदय ने कहा है कि सोची जा रही है ? क्या सोची जा रही है...

श्री ब० रा० भगत: छानबीन हो रही है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कानूनी कार्रवाई करने की बात सोची जा रही है या क्या सोचा जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : छानबीन होगी, एवीडेंस उनका तथा दूसरी जो बाते हैं उनको देख कर कानूनी कार्रवाई की जाती है। वह काम हो रहा है। जहां तक दूसरे अफसरों का सवाल है उनको भी....

डा० राम मनोहर लोहिया : मन्त्रियों का नाम भी नहीं आया है उनकी बात भी नहीं आई है।

श्री मधु लिमये : गृह मन्त्री, रक्षा मन्त्री चह्वाण के, अब वे आ रहे हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब आ रहे हैं भूतपूर्व रक्षा मन्त्री ।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक प्रोसीजर की बात है वह मैं बता रहा हूं । कहां फ़ाइल्ज ज्यादा अटक सकती है और आगे से ऐसी दिक्कत न हो, ऐसी गलती न हो इस तरह की सब बातों के बारे में डायरेक्शन, जब कोई कमेटी रिपोर्ट देती है, दिये जाते हैं और उनका ध्यान उस ओर दिलाया जाता है ।

जहां तक सदन की समिति बिठाने का सवाल है यह सवाल अभी नहीं उठता क्योंकि पी० ए० सी० इन बातों में जा चुकी है और यह कई मन्त्रालयों से सम्बन्धित मामला है । डी० जी० एस० डी० इस में आता है एस० टी० सी० है, कामर्स विभाग है, डिफेंस का मामला है और ये सारे...

Shri Jyotirmoy Basu: Let us cut it short. The question is, has he gone on leave preparatory to retirement or release?

Mr. Speaker: Kindly sit down. The question was long and naturally the answer also would be long. We cannot help it.

श्री ब० रा० भगत पी० ए० सी० की जो सिफारिशें हैं सभी मन्त्रालय उन पर कार्रवाई कर रहे हैं । इसलिए अभी कोई सदन की समिति बनाने या और कोई कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच के लिए अध्यक्ष के नाते आप स्वयं ही एक कमेटी बना सकते हैं ।

दूसरा रास्ता यह है कि जो नई पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी बनने वाली है उसको आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस मामले की वह पूरी जांच करे और अपनी रिपोर्ट सदन के सामने लाये । इस बारे में सारे तथ्यों को सदन के सामने लाना जरूरी है और मैं समझता हूं कि सरकार को भी इस में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक आखिरी राय का...

Mr. Speaker: It is a good idea. We should consider it. Let us go to the next question.

Shri B. R. Bhagat: May I suggest about the procedure?

माननीय सदस्य ने कहा है कि नई कमेटी इसको देखे । मैं उनको बताना चाहता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट जाती है और जो नई कमेटी है वह हमेशा इन चीजों को देख सकती है और जो कार्रवाई होगी उसकी रिपोर्ट भी कमेटी को दी जाती है । यह प्रोसीजर की बात है जो मैं बता रहा हूं ।

Shri H. N. Mukerjee: Sir,....

Mr. Speaker: A suggestion has been made that the new Committee should go into it. I have called the next question.

Shri H. N. Mukerjee: He has not given a categorical assurance. The point is....

Mr. Speaker: It is an important question. But one cannot elicit the whole information. I realise it is an important question and therefore the Public Accounts Committee could naturally go into it and give more details about it.

Shri H. N. Mukerjee: The Public Accounts Committee's report was before the Government for nearly five months and even then, the Minister comes with a very equable statement with regard to this matter and a person who is alleged to be responsible has gone on retirement or something like that. So, the whole matter appears to be so dubious that something has got to be done here

and now and not merely hypothetical assurances about some kind of investigation by the new Public Accounts Committee de novo which would mean a lot of waste of time and other kinds of annoyance.

Mr. Speaker: One cannot elicit the whole information.

Shri H. N. Mukerjee: Sir, I want to ascertain from Government the reasons for the delay in the matter of action over the explicit recommendation of the Public Accounts Committee which took a very grave view of the transactions which were alleged to have taken place. I want to know why Government has delayed doing anything in this matter.

Shri B. R. Bhagat: There has been no delay. The hon. Member is a very old and senior Member. The procedure of the Parliamentary Committee is all laid down. This concerns various departments—the Defence Ministry, the Commerce Ministry and the Supply Department. They all are in communication with the Public Accounts Committee. On their recommendations, action is taken and it is reported to the Committee, and that is why I suggested that the new Public Accounts Committee can always take notice of this and do whatever they think proper. There is nothing wrong.

Mr. Speaker: I think that in the Question Hour, one cannot go much more into it. Perhaps some other method will have to be adopted. It is a very important question. Now, I go to the next question.

चुनाव समाचारों का प्रसारण

+

*60. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने चुनाव परिणामों के प्रसारण के मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मतगणना के दौरान कुछ प्रमुख विरोधी नेताओं के पक्ष में पड़े मतों की संख्या की घोषणा नहीं की गई जबकि प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के पक्ष में पड़े मतों की दिन में कई बार घोषणा की गई; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). आकाशवाणी ने बिल्कुल निष्पक्ष रहने का प्रयत्न किया है। सभी समाचार बुलेटिनों को देखना कठिन है। यदि कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में लाया गया, तो उसकी जांच की जाएगी।

(ग) सवाल नहीं उठता।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव समाचारों के प्रसारण के सम्बन्ध में क्या आकाशवाणी ने पहले से कोई अपनी नीति निर्धारित की थी ? यदि हां, तो क्या उस नीति में कोई ऐसी भी सम्भावनायें थीं कि कुछ व्यक्ति जो जीतेंगे उनके समाचार दो दो दिन लगातार प्रसारित किए जायेंगे तथा और कुछ जो जीतेंगे उनके समाचार एक बार भी कठिनाई से प्रसारित किए जायेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि यदि नीति निर्धारित की थी और उसका जिन अधिकारियों ने पालन नहीं किया उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है ?

Shri K. K. Shah: I can assure the hon. Member, after going through all the records—I am prepared to give proof—that so far as the announcement of results is concerned, AIR has been absolutely impartial.